मिशन वात्सल्य योजना

संदर्भ

हाल ही में मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार धनराशि जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

• मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप है।
• यह बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता के साथ-साथ किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देता है, जिसका आदर्श वाक्य 'किसी बच्चे को नहीं छोड़ना' है।
• देश भर में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देने के लिए यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई है।
• विधायिका के साथ केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः 60:40 के अनुपात में है।
• केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है।
• विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यह 100% केंद्रीय हिस्सा है।

दक्षिण कोरिया का पहला मून ऑर्बिटर अंतरिक्ष में लॉन्च

सन्दर्भ

दक्षिण कोरिया अपने पहले चंद्र ऑर्बिटर के प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा की दौड़ में शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

• दानुरी - जिसका अर्थ है "चंद्रमा का आनंद लेना " - एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से लॉन्च किए गए फाल्कन 9 रॉकेट पर ले जाया गया था।
• इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना है।
• साल भर चलने वाले मिशन के दौरान, दानुरी अनुसंधान करने के लिए छह अलग-अलग उपकरणों का उपयोग करेगा, जिसमें भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइटों की पहचान करने के लिए चंद्र सतह की जांच करना शामिल है।
• एक उपकरण व्यवधान-सहनशील, नेटवर्क आधारित अंतरिक्ष संचार का मूल्यांकन करेगा, जो दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, विश्व में सबसे पहले है।
• यह उपग्रहों या अन्वेषण अंतरिक्ष यान को जोड़ने के लिए एक वायरलेस इंटरनेट वातावरण विकसित करने का भी प्रयास करेगा।
• लूनर ऑर्बिटर नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए के-पॉप सनसनी बीटीएस के गाने डायनामाइट को स्ट्रीम करेगा।
• अगर यह मिशन सफल होता है, तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सातवां देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा की मानवरहित जांच शुरू की है।

हसदेव अरण्य क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन

सन्दर्भ

पिछले एक साल में, इस क्षेत्र में खनन के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य विधेयक पारित किया जिसमें केंद्र से हसदेव क्षेत्र के सभी कोयला खनन ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया गया।

प्रमुख बिंदु

• हसदेव अरण्य वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है।
• हसदेव अरण्य (अरण्य का अर्थ है जंगल) हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 1,878 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
• हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
• हसदेव वन भी हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध के लिए जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो छह लाख एकड़ भूमि को सिंचित करता है, जो राज्य की मुख्य फसल के रूप में धान के साथ महत्वपूर्ण है।
• इसके अलावा, वन उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्ध जैव विविधता और हाथियों के लिए एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं।
• हसदेव अरण्य के नीचे एक कोयला क्षेत्र है जिसमें 22 कोयला ब्लॉक हैं। 2010 में, केंद्र ने हसदेव अरण्य को खनन के लिए "नो-गो" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया।

एक निजी सदस्य संकल्प क्या है?

• गैर-सरकारी सदस्य द्वारा एक निजी सदस्य का प्रस्ताव लाया जा सकता है और यदि पारित हो जाता है, तो यह सदन के विचार की अभिव्यक्ति बन जाता है।
• कृषि कानून आंदोलन के दौरान पंजाब और केरल की राज्य विधानसभाओं द्वारा ऐसे निजी सदस्य प्रस्तावों को पारित किया गया था, जहां दोनों राज्य विधानसभाओं ने तत्कालीन प्रस्तावित (अब वापस ले लिया) कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

सीसीआई को अधिक अधिकार

सन्दर्भ

सरकार ने लोकसभा में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक पेश किया है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के दायरे को प्रभावी ढंग से विस्तृत करता है।

प्रमुख बिंदु

• अधिनियम की धारा 5 में संशोधन के अनुसार 2000 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए सीसीआई की पूर्व स्वीकृति लेने का प्रस्ताव है।
• कई डिजिटल व्यापार लेनदेन, विशेष रूप से बड़ी तकनीक के अपतटीय लेन-देन में बड़ी संपत्ति या टर्नओवर शामिल नहीं होता है, लेकिन उच्च मूल्यांकन के साथ समाप्त होते हैं।
• ये सौदे, अब तक, सीसीआई की जांच के अंतर्गत नहीं आते थे, हालांकि लेन-देन में शामिल कंपनियों के भारत में पर्याप्त व्यावसायिक हित थे।
• वे सीसीआई जांच के दायरे में नहीं आए हैं क्योंकि मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानून में विलय नियंत्रण मानदंड "संपत्ति" और "टर्नओवर" सीमा पर आधारित थे। इसमें डील वैल्यू को मानदंड के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

अन्य प्रमुख परिवर्तन

• प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग के संबंध में जांच के मामलों में निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र का परिचय।
• इससे जांच को जल्द से जल्द बंद करने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी। संयोजनों के अनुमोदन की समय-सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन किया गया।
• संयोजनों के शीघ्र अनुमोदन के लिए आयोग द्वारा 20 दिनों के भीतर प्रथम दृष्टया राय तैयार करना।
• आयोग के समक्ष प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों और प्रमुख पद के दुरूपयोग पर सूचना दाखिल करने के लिए तीन वर्ष की सीमा अवधि की शुरूआत।
• अन्य कार्टेल के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए कम दंड के संदर्भ में चल रहे कार्टेल जांच में पार्टियों को प्रोत्साहित करें।

काला सागर हरित पहल

सन्दर्भ

रूसी-यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार, एक जहाज (एम/वी रजोनी), संयुक्त राष्ट्र समर्थित समझौते, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत, मक्का लेकर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से त्रिपोली के लिए रवाना हुआ।

प्रमुख बिंदु

• जहाज काला सागर पर एक विशेष रूप से साफ किए गए "सुरक्षित मानवीय समुद्री गलियारे" से गुजरा, जिसे रूस द्वारा उभयचर हमलों से बचाने के लिए खनन किया गया था।
• यह पहल तीन काला सागर बंदरगाहों - ओडेसा, कोर्नोमोर्स्क और युज़नी के माध्यम से यूक्रेनी कृषि उपज के निर्यात को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाती है।
• इस पहल में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ रूस और यूक्रेन द्वारा अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल था।
• सौदे के तहत, जहाजों को खनन क्षेत्रों से बचने के लिए यूक्रेन की नौसेना द्वारा निर्देशित किया जाना है।
• फिर वे एक सहमत गलियारे के साथ बोस्फोरस जलडमरूमध्य के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में जाएंगे।

• इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन, रूस और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ स्थापित एक संयुक्त समन्वय केंद्र द्वारा केवल वाणिज्यिक खाद्य पदार्थों और उर्वरकों को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों का निरीक्षण किया जाना है।

महत्व

• युद्ध से पहले यूक्रेन था :
  - रूस, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद, गेहूँ का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।
  - अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील के बाद , मक्के का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक था ।
  - कनाडा के बाद रेपसीड का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था।
  - सूरजमुखी तेल, खली/भोजन और बीज का सबसे बड़ा निर्यातक था।

• 2020-21 में भारत द्वारा आयात किए गए कुल सूरजमुखी तेल में से 80% यूक्रेन से था।

• ताड़, सोयाबीन और सरसों के बाद सूरजमुखी का तेल भारत का चौथा सबसे बड़ा खपत वाला वनस्पति तेल है, जिसका 70% तेल दक्षिणी राज्यों में खपत होता है

एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना

सन्दर्भ

केंद्र 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होने वाली नई विदेश व्यापार नीति (FTP) में लोकप्रिय निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (EPCG) योजना के विस्तार पर विचार कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

• मौजूदा एफ़टीपी, जो 1 अप्रैल, 2015 को पांच साल के लिए लागू हुआ था, को 30 सितंबर, 2022 तक किस्तों में बढ़ा दिया गया था।

• यह योजना निर्माताओं को निर्यात दायित्व के अधीन शून्य सीमा शुल्क पर पूर्व उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन के बाद के लिए पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति देती है।

निर्यात दायित्व

• ईपीसीजी योजना में लगाया गया निर्यात दायित्व दो प्रकार का होता है- विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) और औसत निर्यात दायित्व (एईओ)।

• एसईओ के तहत, एक निर्यातक को ईपीसीजी लाइसेंस जारी होने की तारीख से शुरू होने वाले 6 वर्षों के भीतर बचाए गए वास्तविक शुल्क के 6 गुना के बराबर माल का निर्यात करना होता है।

• एईओ दायित्व में, डीजीएफटी चाहता है कि निर्यातक पिछले वित्तीय वर्षों में पहले से हासिल किए गए निर्यात प्रदर्शन को बनाए रखे।

ईपीसीजी के साथ विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे

• 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर डब्ल्यूटीओ विवाद पैनल ने फैसला सुनाया था कि ईपीसीजी योजना और एसईजेड योजना सहित भारत में कई निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं ने डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी और काउंटरवेलिंग (एससीएम) समझौता उपायों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

• समझौता उन सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है जो निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर हैं।

• संयुक्त राज्य अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत को इस प्रावधान से केवल तब तक छूट दी गई जब तक कि उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,000 डॉलर तक नहीं पहुंच गया।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना

सन्दर्भ

मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना, कर्नाटक की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत की गई थी।

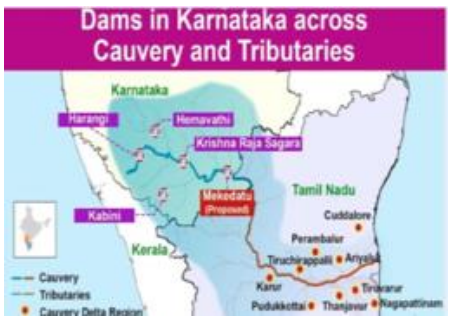

मेकेदातु परियोजना के बारे में

• कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर, बेंगलुरू के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 90 किमी और तमिलनाडु की सीमा से 4 किमी दूर, मेकेदातु (शाब्दिक अर्थ, बकरी की छलांग) के रूप में जाना जाता है, से लगभग 1.5 किमी दूर, ओन्टिगोंडलू में परियोजना आएगी।

• इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरू और आसपास के क्षेत्रों में 4.75 टीएमसीएफ (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पेयजल की आपूर्ति करना है, लेकिन यह 400 मेगावाट की जलविद्युत शक्ति भी उत्पन्न करेगा। इसके लिए कर्नाटक मेकेदातु में 67.16 tmcft की भंडारण क्षमता वाला कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाना चाहता है।

आज़ादीसैट इसरो

सन्दर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए अपना सबसे छोटा व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च करेगा।

प्रमुख बिंदु

• प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा।
• यह भारत के आकर्षक और फलते-फूलते छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रवेश करने के सपने को पूरा करेगा।
• देश के 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव को चिह्नित करने के लिए, (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) एसएसएलवी के पास 'आज़ादीसैट' नामक एक सह-यात्री उपग्रह होगा, जिसमें भारत भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों की 750 युवा छात्राओं द्वारा निर्मित 75 पेलोड शामिल होंगे।
• महत्व: इस परियोजना को विशेष रूप से 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने और युवा लड़कियों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान को अपने करियर के रूप में चुनने के अवसर पैदा करने के लिए संकल्पित किया गया था।

भारत की महिला नौसेना क्रू ने रचा इतिहास

सन्दर्भ

एक अखिल भारतीय नौसेना दल ने डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में समुद्री टोही और निगरानी मिशन को स्वतंत्र रूप से पूरा करके इतिहास रच दिया।

प्रमुख बिंदु

• यह सशस्त्र बलों के लिए एक अनूठी उपलब्धि का प्रतीक है कि केवल महिला अधिकारियों के एक दल ने एक बहु-चालक समुद्री निगरानी विमान में एक स्वतंत्र परिचालन मिशन को अंजाम दिया।
• महत्व: यह उड्डयन संवर्ग में महिला अधिकारियों के लिए अधिक जिम्मेदारी संभालने और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की आकांक्षा रखने का मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है।

जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति (CPCSEA)

सन्दर्भ

सीपीसीएसईए ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से लगभग 159 सफेद चूहों के बचाव को मंजूरी दी, जो बिना ध्यान दिए किए गए जानवरों के परीक्षणों पर सुर्खियों में आ गए।

सीपीसीएसईए के बारे में

• यह पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) की एक वैधानिक समिति है, जिसका गठन पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत किया गया है।
• इसका अधिदेश यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना है कि जानवरों पर प्रयोग करने से पहले, दौरान या बाद में उन्हें अनावश्यक दर्द या पीड़ा का सामना न करना पड़े।
• इस उद्देश्य के लिए, समिति ने जानवरों के प्रजनन और प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 (2001 और 2006 में संशोधित) को प्रयोगशाला पशुओं के प्रयोग, प्रजनन और व्यापार को विनियमित करने के लिए तैयार किया।
• प्रावधानों के तहत, प्रतिष्ठानों को खुद को सीपीसीएसईए के साथ पंजीकृत कराने और संस्थागत पशु आचार समिति (आईएईसी) का गठन करने की आवश्यकता है।
• आईएईसी में सीपीसीएसईए द्वारा मान्यता प्राप्त और पंजीकृत आठ व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें सीपीसीएसईए के एक नामित व्यक्ति भी शामिल हैं।
• छोटे और बड़े जानवरों पर अनुसंधान शुरू करने से पहले क्रमशः आईएईसी और सीपीसीएसईए द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
• पीसीए अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, समिति किसी व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए या अनिश्चित काल के लिए ऐसे किसी भी प्रयोग को करने से रोक सकती है।

किनमेन और हतेरुमा द्वीप

सन्दर्भ

चीन ने ताईवान जलडमरूमध्य में डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें से कुछ जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में हेतेरुमा द्वीप समूह से उतरी।

प्रमुख बिंदु

• हेतेरुमा प्रशांत महासागर में जापान का सबसे दक्षिणी बसा हुआ द्वीप है।
• ताइपे ने यह भी कहा कि ताईवान जलडमरूमध्य में ताइवान-नियंत्रित द्वीपों के समूह किनमेन के बगल में स्थित द्वीपों पर ड्रोन उड़ाए गए थे। इसे क्यूमॉय के नाम से भी जाना जाता है।

विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय के बयान की निंदा की

सन्दर्भ

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के महासचिव द्वारा जारी एक बयान की निंदा की है।

ओआईसी के बारे में

• इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 57 राज्यों की सदस्यता है, जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं।
• ओआईसी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर उनके हितों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज है।
• इसका मुख्यालय सऊदी अरब साम्राज्य के जेद्दाह में है।
• सामान्य सचिवालय: यह ओआईसी का कार्यकारी अंग है और इसे ओआईसी के निर्णय लेने वाले निकायों के निर्णयों को लागू करने का काम सौंपा गया है।
• इसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare